3. पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।

उपरोक्त कथन/कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए-

(a) 3 एवं 4 केवल (b) 1,2 एवं 3 केवल
(c) 1 एवं 4 केवल (d) 1 एवं 4 केवल

Patwar-Exam-2016 (Main) -24.12.2016

Ans. (b) – भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक संस्थाओं के रूप में सशक्त किया और भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में एक नये अध्याय की शुरूआत की। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसरण में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार–

- ग्राम सभा का वर्ष में दो बार आयोजन अनिवार्य है।
- पंचायतीराज के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किये गए हैं।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

224. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था?

(a) 1982 (b) 1990
(c) 1994 (d) 2000

LDC Exam 12.08.2018

Ans. (c) – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 को वर्ष 1994 ई. में संशोधित किया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य था, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया।

225. वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए?

(a) 5 बार (b) 9 बार
(c) 10 बार (d) 11 बार

VDO-2021 Exam Date 27.12.2021 Shift-I

Ans. (d) – वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं का कुल 11 बार चुनाव हो चुका है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ से पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1960 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंचायती विभाग द्वारा निर्वाचन कराये गए।

226. राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था-

(a) 23 मार्च, 1994 ई. (b) 23 अप्रैल, 1994 ई.
(c) 23 जून, 1995 ई. (d) 23जून 1996 ई.

Complier Exam Date-21.08.2016

Ans. (b) – राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल, 1994 ई. लागू किया गया। यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम जाना जाता है। वस्तुतः भारत में पंचायतीराज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 ई. में राजस्थान के नागौर से प्रारम्भ हुआ था। अतः विकल्प (b) सही है।

227.राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है?

(a) ग्राम सेवक (b) पटवारी
(c) सरपंच (d) वार्ड पंच

उत्तर – (a)

RPSC RAS/RTS 2013

व्याख्या – राज्य में राजस्व एवं कानून व्यवस्था के लिए एक ही प्रशासनिक तंत्र गठित किया गया है। राजस्व एवं कानून की व्यवस्था की दृष्टि से राज्य 7 संभागों में विभक्त है। राजस्व संबंधी मामलों में सर्वोच्च निकाय राजस्व मण्डल है, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। राज्य में राजस्व से भिन्न मामलों में पंचायत स्तर पर लोक सुनवाई के रूप में ग्राम सेवकों की नियुक्ति की गयी है।

228.राजस्थान में, एक ग्राम सभा बनती है –

(a) ग्राम-पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से
(b) ग्राम-पंचायत की कार्यकारी समिति से
(c) पंचायत-सर्किल में आने वाले गाँव/गाँवों के पंजीकृत मतदाताओं से
(d) पंचायत-सर्किल में आने वाले गाँव/गाँवों के सभी निवासियों से

उत्तर – (c)

RPSC RAS/RTS 2013

व्याख्या – राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पर एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क मतदाता उसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में वर्ष में 4 बार इसकी बैठक आहूत की जाती है, जबकि प्रत्येक वर्ष में दो बार बैठकें अनिवार्य है।

229. निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम/नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है?

(a) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
(b) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996
(c) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999
(d) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011

उत्तर (d)

RPSC RAS/RTS 2018

व्याख्या- राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 राजस्थान में ग्रामसभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है।